

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 04 जुलाई, 2006

विषय:- मै0 लाल कुंआ स्टोन केशर्स लि0 को सीमेंट कंकीट ब्रिक एवं टाईल्स के निर्माण हेतु तह0 बाजपुर के ग्राम भीकमपुरी एवं बन्नाखेड़ा में कुल 7.283 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-706/सात-स0भू0अ0/2006 दिनांक 24-3-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 लाल कुंआ स्टोन केशर्स लि0 को सीमेंट कंकीट ब्रिक एवं टाईल्स के निर्माण हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(2) एवं उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील बाजपुर के ग्राम भीकमपुरी एवं बन्नाखेड़ा में कुल 7.283 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान

की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जर्गीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157 ए में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

5- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

12- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रा0लि0 देहरादून।
- 6- निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- 7- श्री सौरभ अग्रवाल, निदेशक, लालकुंआ स्टोन केशर्स लि0, रामपुर रोड रुद्रपुर, उद्यमसिंह नगर।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।